

नौबहन और परिबहन मंत्री (श्री बोरेंद्र पाटिल) : (क) 17-11-1974 से।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने जिसकी देखरेख में इस परियोजना पर निर्माण कार्य हो रहा है, कहा है कि यह पुल जिस तारीख से बनना शुरू हुआ था, उस तारीख से लगभग चार साल की अवधि में बनकर तैयार हो जाएगा।

(ग) आरंभ में, 1972 में पुल और पट्टेच मार्गों के निर्माण के लिए 532.87 लाख ₹ का एक अनुमान स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार ने पुल और पट्टेच मार्गों के टेंडर में स्वीकृत मूल लागत और कुछ अन्य तबदीलियों को ध्यान में रखते हुए 815.83 लाख ₹ का एक संशोधित अनुमान सितंबर, 1978 में भेजा था। मंत्रालय में इस अनुमान की जांच की गयी और उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गयीं। इसलिए यह अनुमान राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे इस अनुमान में आवश्यक संशोधन करके मंत्रालय को भिजवाएँ। लेकिन, अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने हाल ही में बताया है कि पुल के निर्माण पर उपरोक्त पिछली बार के संशोधित अनुमान से लगभग 300 लाख ₹ अधिक खर्च होंगे। जब इसकी लागत का ब्यौरेवार अनुमान मंत्रालय में प्राप्त हो जाएगा, तब भारत सरकार इसकी जांच करेगी।

(घ) करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों ने सारा काम 16-11-1978 को पूरा कर देना था। लेकिन, काम इतनी धीमी गति से हुआ कि 16-11-1978 तक सिर्फ 32% काम पूरा हुआ। बाद में यह खबर दी गयी कि भवन क्षेत्र में 24-11-1978 को एक तूफान आया था जिससे ठेकेदारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और कुछ अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। ठेकेदारों ने अब दावा

किया है कि उक्त तूफान के कारण उन्हें जो क्षति पहुँची, उसका उन्हें मूल लागत के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और जो काम बाकी बचा है, उसे पूरा करने के लिए उन्हें बँकी हुई मौजूदा दरों के हिसाब से भुगतान किया जाए। राज्य सरकार इनके दावों की जांचकर रही है। राज्य सरकार पर बराबर जोर दिया जा रहा है कि वह बाकी बचे काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए व्यवस्था करे।

Railway Electrification Programme

*144. SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under a massive electrification programme, Railway propose to bring additional 5,000 to 10,000 kms. under electric traction in the next five years;

(b) if so, the details thereof;

(c) when the work on the project is likely to start; and

(d) the total expenditure involved ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d). The Railways are considering increasing the pace of Electrification of their high density routes. According to the tentative plans, Railways are considering energising about 2900 kms in the VII Plan (1980-85) and commence work on another 3200 kms for completion in the VII Plan, at an approximate cost of Rs. 450 crores. The actual Kilometres to be electrified will, however, depend upon the allocation of funds during the VI Plan period and subject to clearance by the Planning Commission.

Casual Labourers employed by South Eastern Railway

2393. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether permanent casual labourers directly employed by the South Eastern Railway under Departmental arrangement for performing Goods and Parcels Handling work at Shalimar, the biggest goods terminal point on S.E. Railway, went on strike during third week, of June, 1980;